उत्तराखण्ड की आर्थिको का आलोचनात्मक अध्ययन

मनोज पाण्डे,
शोधार्थी, वाणिज्य,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

सारांश

निम्न क्षेत्रीय विकास दर और बढ़ती क्षेत्रीय विषमताएं गरीबी और असमानता की समस्याओं को बढ़ाती हैं जो आर्थिक विकास हेतु किए गए विभिन्न प्रयासों आर सुधारों को धीमा कर देती है, इसलिए आर्थिक विकास दर को सततता बनाए रखना भारत सरकार के लिये चुनौतीपूर्ण हो गया है। जहां एक ओर आर्थिक विकास से संबंधित आँकड़े नवसृजित उत्तराखण्ड राज्य को बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करते है तो वहीं उत्तराखण्ड राज्य से रोजगार के अभाव में पलायन करने वालों कि बढ़ती संख्या आर्थिक विकास के आंकड़ों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आर्थिक विकास के इन्हीं विरोधाभासों के विश्लेषण हेतु प्रस्तुत अध्ययन द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक विकास संबंधी विभिन्न द्वितीयक समकों का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना

1991 में बाजारोन्मुख नीतिगत सुधारों के क्रियान्वयन के बाद से, भारत ने विकास दर में तेज वृद्धि दर्ज को है। निम्न क्षेत्रीय विकास दर और बढ़ती क्षेत्रीय विषमताएं गरीबी और असमानता की समस्याओं को बढ़ाती हैं जो आर्थिक विकास हेतु किए गए विभिन्न प्रयासों आर सुधारों को धीमा कर देती है, इसलिए आर्थिक विकास दर को सततता बनाए रखना भारत सरकार के लिये चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसी ही एक चुनौती राज्यों में संतुलित विकास दर को प्राप्त करना है। जहां एक ओर आर्थिक विकास से संबंधित आकड़े नवसृजित उत्तराखण्ड राज्य को बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करते है तो वहीं उत्तराखण्ड राज्य से रोजगार के अभाव में पलायन करने वालों कि बढ़ती संख्या आर्थिक विकास के आंकड़ों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आर्थिक विकास के इन्हीं विरोधाभासों के विश्लेषण हेतु प्रस्तुत अध्ययन द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक विकास संबंधी विभिन्न द्वितीयक समकों का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है।

भारत के उत्तर–पश्चिमी भाग में स्थित भारतीय गणतंत्र के 27 वें राज्य उत्तराखंड (नवोदित पर्वतीय) को 9 नवंबर, 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर स्थापित किया गया था, जिसकी सीमाऐं उत्तर–पूर्व में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, उत्तर–पश्चिम में भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिण–पूर्व में नेपाल और दक्षिण और दक्षिण–पश्चिम में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से लगी हुई

है। इसकी राजधानी देहरादून में है। उत्तराखण्ड का शाब्दिक अर्थ उत्तरी भू भाग का रूपान्तर है। इस नाम का उल्लेख प्रारम्भिक हिन्दू ग्रन्थों में मिलता है, जहाँ पर केदारखण्ड (वर्तमान गढ़वाल) और मानसखण्ड (वर्तमान कुमांऊँ) के रूप में इसका उल्लेख है। उत्तराखण्ड को 'देवभूमि' के नाम से भी अलंकृत किया जाता है क्योंकि यह समग्र क्षेत्र धममय और दैवशक्तियों की क्रीड़ाभूमि तथा हिन्दू धर्म के उद्भव और महिमाओं की सारगर्भित कुंजी व रहस्यमय है।[1] उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जिसमे इसे देवभूमि एवं मनीषियों की तपोभूमि कहा गया है। स्कन्दपुराण में 5 हिमालयी खंडो (केदारखंड, मानसखंड, नेपाल, जालंधर तथा कश्मीर) का उल्लेख है जिनमे से दो केदारखंड (गढ़वाल) तथा मानसखंड (कुमाऊँ) उत्तराखंड में स्थित है। पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र के लिए उत्तर–खंड, खसदेश एवं ब्रह्मपुर आदि के नामां का तथा बौध साहित्य के पाली भाषा वाले ग्रंथो में उत्तराखंड के लिए 'हिमवंत' शब्द प्रयुक्त किया गया है।

उत्तराखंड की आर्थिको

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कृशि, बागवानी, प"ुपालन, विनिर्माण, निमार्ण, व्यापार, पर्यटन अतथा अन्य सेवा क्षेत्रों पर निर्भर है। उत्तराखण्ड राज्य के दो जनपद पूर्णतः मैदानी, चार जनपद आंशिक मैदानी तथा सात जनपद पूर्णतः पर्वतीय हैं। अतः भौगोलिक प्रतिकूलता के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में वृहद् स्तर पर औद्योगीकरण को प्रोत्साहित नहीं किया जा सका है, परन्तु पूर्णतः मैदानी जनपदों में बड़ी संख्या में वृहद् एवं मध्यम स्तरीय उद्योग स्थापित किए गये हैं। राज्य गठन के प"चात उत्तराखण्ड़ की आर्थिक सोच व आर्थिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आया है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में उद्योगों के विकास हेतु 8 जुलाई 2001 को औद्योगिक नीति बनायी गई[2] तथा जनवरी 2003 में उत्तराखण्ड राज्य के लिए 35,000 करोड़ के केन्द्रीय औद्योगिक पैकेज की घोषणा की गयी थी।[3] राज्य में ना केवल व्यापारिक व वाणिज्यिक गतिविधियाँ तीव्र हुई हैं, वरन् समन्वित आर्थिक प्रगति हेतु अन्य क्षेत्रों का भी विकास हो रहा हैं। राज्य की विकास दर में वर्श 2016–17 में 6.95 प्रति"ात की वृद्धि ऑकी गयी जबकि 2016–17 में प्रचलित एवं स्थिर भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद क्रम"ाः रू0 1,95,606 तथा रू0 1,62,451 करोड़ आंकलित हुआ। प्रचलित भावों पर वर्श 2016–17 में हरिद्वार जिले का सकल घरेलू उत्पाद सर्वाधिक रू0 58,168.24 करोड़ तथा रूद्रप्रयाग का सबसे कम रू0 2510.40 करोड़ आंकलित हुआ था। हरिद्वार जनपद के संबन्ध में यह उल्लेख करना आव"यक है कि पृथक राज्य

[1] Parikrama Uttrakhand. (n.d.). India: Diamond Pocket Books (P) Limited.

[2] पारूप, औधोगिक नीति, 2001, उत्तरांचल भाासन, देहरादून

[3] लोके"ा नवानी एवं अन्य, उत्तराखण्ड इयर बुक, 2013, विनसर पब्लि"िंग कं0 देहरादून ,पृ0सं0 51

के रूप में उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए बनी कौ"ाक समिति की सिफारि"ाों में हरिद्वार जनपद को सम्मिलित भी नहीं किया गया था। वैसे भी हरिद्वार जनपद क निवासियों का उत्तराखंड के पर्वतीय लोगों के साथ पूर्व से किसी प्रकार का सांस्कृतिक एवं भाशाई मेल–मिलाप नहीं रहा है। इस वर्श, राज्य की प्रति व्यक्ति आय विगत वर्श 2015–16 की तुलना में 9.6 प्रति"ात बढ़कर रू0 1,08,370 हो गयी थी।[4] जनपदवार वि"लेशण करने पर ज्ञात हुआ कि इस वर्श जनपद हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय रू0 2,54,050 के सापेक्ष जनपद रूद्रप्रयाग की प्रति व्यक्ति आय मात्र रू0 83,581 की ही थी। इससे स्पश्ट है कि पर्वतीय राज्य उत्तराखंड की जी0डी0पी0 एवं प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में प्रमुख योगदान उसके मैदानी जनपदों का है। संरचनात्मक दृश्टि से वर्श 2017–18 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 10.50 प्रति"ात, द्वितीयक क्षेत्र का 49.74 प्रति"ात तथा तृतीयक या सेवा क्षेत्र का योगदान 39.76 प्रति"ात था। वर्श 2017–18 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को वि"लेशित करने पर अन्य सेवाऐं (12.56%), परिवहन, संचार एवं प्रसारण सेवाऐं (11.65%), निर्माण उद्योग (10.66%) तथा बिजली, गैस, पानी एवं अन्य उपयोगी सेवाऐ (10.45%) में उच्च वृद्धि दर ऑकी गयी थी जबकि कृशि, वन्य एवं मत्स्य क्षेत्र (1.35%) एवं विनिर्माण क्षेत्र (4.6%) में निम्न वृद्धि दर ऑकी गयी थी। इससे स्पश्ट है कि राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः सेवा क्षेत्र पर निर्भर है। इसका कारण उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय भूगोल में पांरपरिक एवं अलाभदायक कृशि तथा उद्योग भून्यता का होना है। दिसम्बर 2017 तक राज्य में कुल 2,290 बैक भााखाओं का नेटवर्क था जिनमें 49% बैंक भााखाऐं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित थीं।

सामाजिक आर्थिक विकास के पांच प्रमुख घटक मूलभूत सुविधायें, जनसांख्यिकी, ि"ाक्षा, चिकित्सा एवं पुश्टाहार तथा आर्थिक स्तर का वि"लेशण करने पर प्राप्त समग्र सूचकांक के आधार पर चिकित्सा और पुश्टाहार को छोड़कर भोश सभी सूचकांकों में 03 मैदानी जनपद उधम सिंह नगर, हरिद्वार एवं देहरादून (अर्ध पर्वतीय) की रैंकिंग क्रम"ाः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रही है।[5] राज्य के मैदानी व भाहरी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ी व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और सामाजिक आर्थिक विशमताओं की प्रबलता भी अधिक है। राज्य स्थापना के बाद आर्थिक विकास की गति में तेजी आने के बावजूद विकास का संकेन्द्रण मैदानी क्षेत्रों में होने के कारण पर्वतीय एवं मैदानी जनपदों में अत्यधिक अर्न्तजनपदीय विशमताऐं बढ़ी हैं पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का मैदानी क्षेत्रों की ओर तेजी से पलायन भी हुआ है।[6] राज्य सरकार ने इन औद्योगिक इकाईयों को आकर्षित करने

[4] https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/per-capita-income-up-by-10-in-uttarakhand/articleshow/65359053.cms
[5] https://des.uk.gov.in/files/Identification_of_Level_of_Development(District-wise_and_Block-wise)_in_Uttarakhand.pdf
[6] https://des.uk.gov.in/files/Aarthik_Sarveshan_-_Single_Pgs_All.pdf साभार

के लिए आयकर, प्रवेश शुल्क आदि में छूट तथा पूंजीगत विनियोग हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रावधान किए हैं। साथ ही औद्योगिक इकाईयों में श्रमिकों तथा कर्मचारियों के 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की नीति बनाई है। परिणामस्वरूप राज्य में औद्योगिक विकास की दर में वृद्धि तो हुई है, किंतु आज भी प्रदेश असंतुलित औद्योगिक विकास की समस्या का सामना कर रहा है तथा पर्वतीय क्षेत्र लगभग उद्योग शून्यता की स्थिति में हैं। पदे"ा व केन्द्र सरकार द्वारा इस पर्वतीय प्रदे"ा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को दिये गये प्रोत्साहनों एवं रियायतों के सम्बन्ध में यह स्पश्ट करना भी आव"यक है कि अधिका"ा उपक्रमों की स्थापना इन्हीं प्रोत्साहनों एवं रियायतों का लाभ उठाने के लिए की गयी थी और उद्योग की स्थापना के नाम पर यहॉ अधिका"ातः कोडांतरण एवं पैकिंग का ही कार्य हुआ। स्थिति यह है कि रियायत एवं प्रोत्साहन काल के समाप्त होने के बाद आज अनेक उपक्रमों ने अपना व्यवसाय समेटना प्रारम्भ कर दिया है। यही स्थिति पर्वतीय एवं स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने की भी है, जिसमें ठेके पर श्रमिक (अकु"ाल) वर्ग के रूप में स्थानीयों को रोजगार प्रदान किया गया है परन्तु प्रबन्ध, तकनीकी एवं पर्यवेक्षकीय प्रवृत्ति के कार्यों में दूसरे प्रदे"ाों के लोग ही कार्यरत हैं।

उत्तराखण्ड में लोहा, ताँबा, चूना, पत्थर, डोलामाइट, मेग्नेसाइट एवं सोप स्टोन, जिप्सम, फास्फोरस, बैराइट्स, एम्बेस्टॉस, रॉक फास्फेट, सीसा, चाँदी एवं सैलखड़ी तथा नदियों के रेत तथा पत्थर के भण्डार आदि खनिजों का विशाल भण्डार विद्यमान है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्श 2001 में खनिज नीति का निर्माण किया गया तथा इसमें वर्ष 2002, 2007, 2008 तथा 2011 में आवश्यकतानुसार संशोधन किए गये ताकि खनिज सम्पदा का लाभप्रद एवं वैज्ञानिक विदोहन किया जा सके। वर्तमान समय में दाबका नदी घाटी एवं कोटा दून में खनिज तेल की संचित राशि की संभावना है, जिसकी खोज की जा रही है। राज्य सरकार की खनिज नीति के अनुसार वनीय क्षेत्रों में खनन का कार्य 'उत्तराखण्ड वन विकास निगम' तथा राजस्व क्षेत्रों में गढ़वाल एवं कुमाऊँ मंडल विकास निगम द्वारा किया जाता है।[7] परन्तु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि उत्तराखण्ड में खनिज सम्पदा पर खनन माफियाओं का इतना बड़ा नियन्त्रण है कि उनके समक्ष प्रायः सरकार भी लाचार सी प्रतीत होती है।

जल विद्युत की अपार संभावनाओं के कारण उत्तराखण्ड को भारत का भावी पावर हाउस कहा जाने लगा है। सर्वेक्षणों से यह स्पष्ट हुआ है कि उत्तराखण्ड की सभी छोटी–बड़ी नदियों में 20,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादित की जा सकती है। वर्तमान में राज्य में लगभग 4200

[7] लोके"ा नवानी एवं अन्य, उत्तराखण्ड इयर बुक, 2013, विनसर पब्लि"ांग कं0 देहरादून ,पृ0सं0 389

मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाऐं निर्माणाधीन हैं।[8] प्रदेश की नई जलविद्युत नीति के अर्न्तत 100 मेगावाट तक की परियोजनाओं का आबंटन प्रतिस्पर्धात्मक निविदा से किया जा रहा है। उत्तराखण्ड जलविद्युत निगम, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, एन0एच0पी0सी0, एन0टी0पी0सी0 एवं टी0एच0डी0सी0 आदि संस्थाओं की उत्तराखण्ड को ऊर्जा प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अपार जलविद्युत संभावनाओं वाले इस प्रदेश में प्रायः यह बहस चलती रहती है कि यहाँ होने वाली भौगोलिक एवं भूगर्भीय हलचलों को ध्यान में रखते हुए वृहद् स्तरीय विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित ना किया जाये, अपितु इनके स्थान पर लघु परियोजनाओं का निर्माण किया जाये, जिससे यहाँ पर्यावरण संतुलन तो बना ही रहेगा, साथ ही स्थानीय जनता को भी इन परियोजनाओं से अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के अवसर प्राप्त होंगें[9]।

राज्य का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय होने के कारण यहाँ परिवहन का मुख्य स्रोत सड़कें ही हैं। उत्तराखण्ड में निर्मित पक्की सड़कों की कुल लम्बाई 21,490 किमी0, जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी सड़कों की लम्बाई 17,772 किमी0 तथा स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित सड़कों की लम्बाई 3925 किमी0 है। परन्तु अभी तक राज्य के लगभग 60 प्रतिशत आबाद गाँव ही सड़क मार्ग से जुड़ सके हैं। राज्य के परिवहन विभाग को वर्ष 2000–01 में 5602.7 लाख की आय प्राप्त हो रही थी, जो वर्श 2012–13 में बढ़कर रू0 29816.82 लाख हो गयी है।[10] राज्य का मैदानी भाग रेलवे यातायात से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं–देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार, ऋषिकेश, रूड़की, लक्सर, टनकपुर, काठगोदाम, लालकुआँ, रामनगर आदि। राज्य में प्रायः देहरादून तथा काठगोदाम से ही लम्बी दूरी की रेल सेवा संचालित होती हैं। राज्य गठन के पश्चात यहाँ हवाई अड्डों एवं हवाई पट्टियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देहरादून के जौलीग्रांट, ऊधमसिंह नगर के पंतनगर, चमोली के गोचर, पिथौरागढ़ के नैनी–सैनी तथा उत्तरकाशी में ना केवल हवाई अड्डों एवं हवाई पट्टियों का निर्माण हो चुका है, बल्कि यहाँ से वि"ोश परिस्थितियों में हवाई सेवाऐं भी संचालित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में केदारनाथ धाम के लिए भी हेली सेवा संचालित हो चुकी है।

कृषि क्षेत्र में राज्य की स्थिति अत्यन्त विषम है। एक ओर यहाँ, कृषि का मुख्य क्षेत्र राज्य का तराई–भाबर क्षेत्र है, जो कि व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों की दृष्टि से वैसे ही समृद्ध है तो दूसरी ओर यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र की 90 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी अलाभदायक व परम्परागत

[8] https://www.downtoearth.org.in/hindistory/river/dam/a-study-of-what-people-say-about-uttarakhand-s-hydropower-projects-75485

[9] http://ahec.org.in/wfw/pdf/Hydropower_stations_in_operation_and_under_construction_in_uttarakhand.pdf

[10] http://transport.uk.gov.in/pages/display/62-statistical-data

कृषि पर ही निर्भर है। उत्तराखण्ड में केवल 7.4 लाख हैक्टेयर भूमि (लगभग 14 प्रति"ात) पर ही कृषि कार्य हो पा रहा है।[11] वर्ष 2010–11 में उत्तराखण्ड में कृषि उपयोग में लाया गया कुल क्षेत्र 7,23,164 हैक्टेयर था, जिसमें पर्वतीय जनपदों का 4,62,927 तथा मैदानी जनपदों का 2,60,237 हैक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है। राज्य में वर्श 2010–11 में अनाजों का 17,37,499 मीट्रिक टन, दालों का 45,876 मीट्रिक टन, तिलहनों का 25,320 मीट्रिक टन तथा अन्य कृशि उत्पादों (गन्ना इत्यादि) का 62,35,474 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। यहाँ कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत बागवानी का उल्लेख ना करना त्रुटिपूर्ण होगा। राज्य की भौगोलिक एवं जलवायुगत परिस्थितियाँ बागवानी के लिए सर्वथा उपयुक्त है तथा परम्परागत कृषि की तुलना में यहाँ के कृषकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में बागवानी एक मजबूत आधार बन सकती है जिनके विस्तार की पर्याप्त संभावनाऐं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड सरकार ने यहाँ के कृषि एवं बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लीची, बासमती चावल, पुष्प तथा जड़ी–बुटियों को निर्यात क्षेत्र के अर्न्तगत सम्मिलित किया है। साथ ही जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि फल उत्पादन की दृष्टि से हिमांचल प्रदेश से अच्छी भौगोलिक एवं जलवायुगत परिस्थितियाँ विद्यमान होन के पश्चात भी यहाँ के परम्परागत बागानों का भौगोलिक क्षेत्र सिमटता जा रहा है तथा उनका स्थान राज्य में भू–माफियाओं द्वारा स्थापित कंकरीट के जंगल ले रहे हैं।

राज्य का 34651 वर्ग किमी0 (64.79 प्रतिशत) भू–भाग वनाच्छादित है, जिसमें 6 राष्ट्रीय पार्क, 6 वन्यजीव विहार तथा 3 संरक्षित क्षेत्र है, जिनका विस्तार 7376 वर्ग किमी0 तक है। राज्य में वनों का विस्तार मैदानी क्षेत्र की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक है। यहाँ 25,000 प्रकार की वनस्पतियाँ पायी जाती हैं। राज्य में इस समय कुल 13 वृत्त, 44 प्रभाग, 284 रेंज, तथा 1569 बीट हैं।[12] वन उपज से अनेक प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्योगों को कच्चा माल, इमारती लकड़ी, लीसा, बाँस आदि प्राप्त होता है। राज्य में 32 वन विभाग इकाईयाँ स्थापित हैं, जिनके अन्तर्गत 1254 वन प्रबंध समितियाँ सचालित हैं। पिछले कुछ समय से राज्य में वनों का क्षेत्रफल निरन्तर कम होता जा रहा है। इसका कारण राज्य में बढ़ता भवन व सड़क निर्माण, औद्योगीकरण एवं जलविद्युत परियोजनाऐं आदि हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड के वन केवल लकड़ी, जडी–बूटियों, चारे व औद्योगिक कच्चे माल के स्रोत ही नहीं हैं, वरन यहाँ के लोगों के आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक आधार भी हैं। इतना ही नहीं ये समस्त भारत की पारिस्थितिकी

[11] http://agriculture.uk.gov.in/

[12] लोके"ा नवानी एवं अन्य, उत्तराखण्ड इयर बुक, 2013, विनसर पब्लि"िंग कं0 देहरादून ,पृ0 सं0 391

को संतुलित रखने के आधार स्तंभ हैं, जिनके प्रति संवेदनशील होना न केवल राज्यवासियों, वरन केन्द्र व राज्य सरकार का सर्वप्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

इस हिमालय क्षेत्र में जड़ी–बूटियों की अपार सम्पदा है। सरकार ने राज्य को 'हर्बलस्टेट' बनाने का लक्ष्य निर्धरित किया है, तथा इसके लिये अनेक स्थानों पर हर्बल पार्कों की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार ने चमोली के गोपेश्वर में जड़ी–बूटी संस्थान की स्थापना की है।[13] इस हेतु 358 हैक्टेयर वन क्षेत्र को जड़ी–बूटी उत्पादन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। अभी हाल में ही इसी तरह का सार्थक प्रयास सितारगंज (ऊधमसिंह नगर) में भी किया गया है। भविष्य में प्रत्येक वर्ष 400 मीट्रिक टन जड़ी–बूटी के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ की स्थापना ने राज्य के लोगों का ध्यान जड़ी–बूटी उत्पादन की और आकर्षित किया है। इसके अतिरिक्त जड़ी–बूटी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के सर्वश्रेष्ठ साधन के रुप में सरकार को अधिकतम पर्यटन स्थलों पर, यदि संभव हो तो हर्बल गार्डन या जड़ी–बूटी पौधशालाओं की स्थापना करने का प्रयास करना चाहिये। इससे ना केवल राज्य की ओर पर्यटकों का ध्यान आकर्षित होगा, बल्कि जड़ी–बूटी उत्पादन आर्थिक दृष्टि से भी अधिक उपयोगी बन सकेगा। जड़ी–बूटी उत्पादन के साथ ही उत्तराखण्ड में ब्रिटिश काल से स्थापित चाय बागानों को पुनः विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत जनपद नैनीताल में 550 हैक्टेयर, अल्मोड़ा में 1310 हैक्टेयर, पिथौरागढ़ में 100 हैक्टेयर, चम्पावत में 950 हैक्टेयर, चमोली में 1010 हैक्टेयर, बागेश्वर में 930 हैक्टेयर, रूद्रप्रयाग में 250 हैक्टेयर, पौड़ी में 100 हैक्टेयर तथा देहरादून में 700 हैक्टेयर क्षेत्र में चाय बागान स्थापित किए गये हैं।

उत्तराखण्ड की आर्थिकी के उपरोक्त घटकों के साथ ही सेवा क्षेत्र की भी राज्य की आर्थिकी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें भी तुलनात्मक रुप में पर्यटन क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, यात्रा एवं परिवहन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन आदि सम्मिलित हैं। विगत दशक (2014–15) में सेवा क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50 प्रतिशत योगदान रहा है।[14]

उत्तराखण्ड, प्राचीनकाल से ही ऋषि–मुनियों और योगियों की साधना स्थली एवं पर्यटन क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र की सुरम्य घाटियों और वनों से ढकी पर्वत चोटियों के एकांत एवं शांत वातावरण में ही उनके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर शिक्षा का प्रचार–प्रसार किया गया। आज यही हिमालय भौतिकतावादी दौड़ से थके–हारे शहरी लोगों के लिये पर्यटन एवं पर्वतारोहण का आकर्षण बना

[13] https://www.amarujala.com/dehradun/151145705020144-602-1828-gopeshwar-news

[14] https://navbharattimes.indiatimes.com/business/business-news/uttarakhand-is-ahead-of-all-states-in-industry-and-service-sector-growth-says-assocham/articleshow/53567994.cms

हुआ है। ये पर्यटक, पर्वतारोही, ट्रेकर, प्रकृति प्रेमी, छायाकार, कलाकार, कवि, जन्तु विशेषज्ञ, वैज्ञानिक एवं भूगोलवेत्ता कोई भी हो सकते हैं। चूंकि उत्तराखण्ड में उपरोक्त सभी प्रकार के जिज्ञासुओं के लिए प्रकृति प्रदत्त पर्यटन उत्पाद विद्यमान हैं, अतः कहा जा सकता है कि उत्तराखण्ड में पर्यटन की पर्याप्त संभावनाऐं विद्यमान हैं। राज्य के जी0डी0पी0 में वर्श 2017–18 में पर्यटन क्षेत्र का कुल योगदान 13.57% था। इस वर्श राज्य में आये कुल पर्यटकों की संख्या 347.23 लाख थी जिनमें से 1.42 लाख पर्यटक विदे"ाी थे।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में पर्यटकों की आवक में अप्रत्या"ाित कमी का मुख्य कारण उत्तराखण्ड में 15 से 17 जून 2013 के मध्य केदारनाथ में आयी जलप्रलय के नाम से विख्यात दैवीय आपदा थी, जिसमें दे"ा–विदे"ा के 5000 से अधिक पर्यटकों (तीर्थयात्रियों) को काल का ग्रास बनना पड़ा। उक्त आपदा का दूरगामी प्रभाव उत्तराखण्ड के पर्यटन व्यवसाय पर लम्बे समय तक पड़ने की संभावना है। राज्य में पर्यटन विकास परिषद की स्थापना की गयी है। सरकार द्वारा जहाँ एक ओर स्थापित पर्यटन स्थलों में अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य किया जा रहा है, वहीं पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए अर्थात सतत् विकास की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए नवीन पर्यटन स्थलों का विकास भी किया जा रहा है। साथ ही पर्यटन योजनाओं में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनि"चत करने के प्रयास किये जा रहे हैं। स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक अद्वितीय पर्यटन विकास योजना 'वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना' नाम से प्रारम्भ की गयी है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पर्यटन विकास हेतु राज्य को केन्द्र सरकार से रू0 300 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई। इन्हों प्रयासों का परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में उत्तराखण्ड में पर्यटन 168 प्रतिशत बढ़ा है। राज्य के कुल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के योगदान का 60 प्रतिशत अंश पर्यटन व्यवसाय से ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों में सर्वाधिक लोग धार्मिक पर्यटन के लिए आते हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास महायोजना (2007–22) बनायी गयी है, जिसमें 25–35 आयु वर्ग के 37 प्रतिशत तथा 35–45 आयु वर्ग के 24 प्रतिशत पर्यटकों को उत्तराखण्ड में आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य में युवाओं को आकर्षित कर धार्मिक पर्यटन के अतिरिक्त साहसिक एवं ईको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उत्तराखण्ड में पर्यटन विकास को नया आयाम मिल सके।

निष्कर्ष

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कृशि, बागवानी, प"ुपालन, विनिर्माण, निमार्ण, व्यापार, पर्यटन तथा अन्य सेवा क्षेत्रों पर निर्भर है। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः सेवा क्षेत्र पर निर्भर है। इसका कारण उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय भूगोल में पांरपरिक एवं अलाभदायक कृशि तथा उद्योग भून्यता का होना है। राज्य के मैदानी व भाहरी क्षेत्रों की अपक्षा पहाड़ी व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और सामाजिक आर्थिक विशमताओं की प्रबलता भी अधिक है। राज्य स्थापना के बाद आर्थिक विकास की गति में तेजी आने के बावजूद विकास का संकेन्द्रण मैदानी क्षेत्रों में होने के कारण पर्वतीय एवं मैदानी जनपदों में अत्यधिक अन्तजनपदीय विशमताऐं बढ़ी हैं। फल उत्पादन की दृष्टि से हिमांचल प्रदेश से अच्छी भौगोलिक एवं जलवायुगत परिस्थितियाँ विद्यमान होने के पश्चात भी यहाँ के परम्परागत बागानों का भौगोलिक क्षेत्र सिमटता जा रहा है राज्य की भौगोलिक एवं जलवायुगत परिस्थितियाँ बागवानी के लिए सर्वथा उपयुक्त है तथा परम्परागत कृषि की तुलना में यहाँ के कृषकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में बागवानी एक मजबूत आधार बन सकती है जिनके विस्तार की पर्याप्त संभावनाऐं हैं। राज्य में युवाओं को आकर्षित कर धार्मिक पर्यटन के अतिरिक्त साहसिक एवं ईको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उत्तराखण्ड में पर्यटन विकास को नया आयाम मिल सके।